



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

18 AASHADH 1947 (S)

No. 327

RANCHI WEDNESDAY 9th JULY, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

9th July, 2025

Notification No.- 18/2024 – State Tax

S.O. No. 17, Dated 9th July, 2025:- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 171 read with sub-section (1) and second proviso to sub-section (5) of section 109 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby empowers the Principal Bench of the Appellate Tribunal, constituted under sub-section (3) of section 109 of the said Act, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by that registered person.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of October , 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar,
Commissioner,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संo.18/2024- राज्य कर

एस. ओ. सं. 17, दिनांक 9 जुलाई, 2025 - झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 171 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 109 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के साथ पठित माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन गठित, अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ को, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिये गये इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कटौती वास्तविक रूप से उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदाय की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में समरूप कटौती में परिणत हुई है की जांच करने के लिए सशक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2024 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग।